

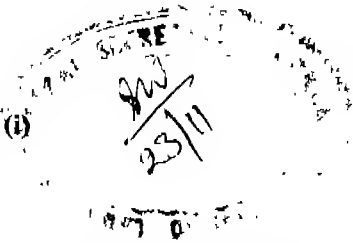


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 318]  
No. 318]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, जून 15, 1989/ज्येष्ठ 25, 1911  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 1989/JYAISTHA 25, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1989

आयकर

सा.का.नि. 626 (अ) —नौवो और वायुयानों का परिचालन करने वाले उद्यमों की आय के संबंध में दोहरे कराधान के परित्यक्त के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से मूल्य करार, सत्रिदाकारी राज्या द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से तारीख 12 अप्रैल, 1989 का प्रवृत्त हो गया है;

अब, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 13) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तिवाता प्रयोग करने हुए विदेश देशों के कि उक्त करार के सभी उपबन्धों का भारत में कार्य-निष्ठ किया जाएगा।

अनुबंध (आदान-प्रदान किए गए पत्र यहाँ संलग्नस्थानित किए जाएंगे)

[का.नं. 501/3/86-कि.क.प्र. (अधिसूचना नं. 8391)]  
पी के अण्णाबू, संयुक्त सचिव

अनुबंध

संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास,  
नई दिल्ली, 12 अप्रैल 1989

महामहिम,

मुझे यह प्रस्ताव करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि जलयानों और वायुयानों के अन्तराष्ट्रीय परिचालन से दूसरे देश के निवासियों द्वारा प्राप्त आय का आयकर में मुक्त करने के लिए दोनों सरकारों द्वारा पारस्परिक प्राधिकार पर एक करार किया जाए। इस करार की शर्तें निम्नानुसार हैं —

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार आन्तरिक राजस्व संहिता की धारा 872(बी) और 883(ए) के अनुसार भारत के निवासियों व्यक्तियों का (संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों से भिन्न) और भारत में संगठित निधियों का जलयानों तथा वायुयानों के अन्तराष्ट्रीय परिचालन से प्राप्त आय का वर से छूट देने के लिए सहमत है। यह छूट संयुक्त राज्य

अमेरिका के नागरिकों को (जो भारत के नागरिक नहीं हैं) और संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठित निगमों को (जिन पर निवास के आधार पर भारत द्वारा कर नहीं लगाया जाता है) भारत द्वारा प्रदान की गई समतुल्य छूटों के आधार पर प्रदान की जाती है।

भारत सरकार  
जित्त मंत्रालय,  
राजस्व विभाग नई दिल्ली,  
दिनांक 12 अप्रैल, 89

किमी निगम के मामले में, यह छूट केवल तभी लागू होगी यदि निगम निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करता हो।

महामहिम,

(1) ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निगम के आधे से अधिक मूल्य का स्टॉक धारण करने हों जो भारत के निवासी हों अथवा किसी ऐसे अन्य देश के निवासी हों जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों और निगमों को पारस्परिक छूट प्रदान करता है; अथवा

मुझे यह प्रस्ताव करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि जलयानों और वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से दूसरे देश के निवासियों द्वारा प्राप्त आय को आयकर से मुक्त रखने के लिए दोनों सरकारों द्वारा पारस्परिक आधार पर एक करार किया जाए। इस करार की शर्तें निम्ना-नुसार हैं :—

(2) निगम के स्टॉक का मूलतः और नियमित रूप से भारत में किसी स्थापित सेक्यूरिटी बाजार में व्यापार किया जाता है अथवा निगम का स्टॉक किसी ऐसे निगम द्वारा पूर्णतः धारित है जिसके स्टॉक का उसी प्रकार व्यापार किया जाता हो और जो भारत में संगठित भी हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार आन्तरिक राजस्व संहिता की धारा 872 (बी) और 883(ए) के अनुसार भारत के निवासी व्यष्टियों को (संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों से भिन्न) और भारत में संगठित निगमों को जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से प्राप्त सकल आय को कर से छूट देने के लिए सहमत है। यह छूट संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को (जो भारत के नागरिक नहीं हैं) और संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठित निगमों को (जिन पर निवास के आधार पर भारत द्वारा कर नहीं लगाया जाता है) भारत द्वारा प्रदान की गई समतुल्य छूटों के आधार पर प्रदान की जाती है।

उप पैराग्राफ (1) के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार को भारत के किमी व्यष्टि निगमों के रूप में समझा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कर से छूट के प्रयोजनों के लिए, उप पैराग्राफ (1) का समाधान किया जाना तभी समझा जाएगा यदि वह निगम आन्तरिक राजस्व संहिता के अधीन कोई "निधनित विदेशी निगम" है।

किमी निगम के मामले में, यह छूट केवल तभी लागू होगी यदि निगम निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करता हो :

सकल आय में जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से प्राप्त सभी प्रकार की आय भी शामिल है जिसमें जलयानों अथवा वायुयानों के पूर्णकालिक या जलयानों की अवधि के आधार पर किराए से हुई आय भी शामिल है। इस आय में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त जलयानों और वायुयानों के बेअरबोट के आधार पर किराए से हुई आय, अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त आवाहनों और उनसे संबंधित उपकरणों के किराए से प्राप्त आय, और जलयानों अथवा वायुयानों की बिक्री पर प्राप्त लाभ भी शामिल है, बशर्ते प्रत्येक मामले में वह आय जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन के कारण प्राप्त हुई प्रासंगिक आय हो। जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से होने वाली सकल आय में किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन अभिकरण में भाग लेने से उद्भूत आय और जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित निधियों पर प्राप्त होने वाला व्याज भी शामिल है।

(1) ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निगम के आधे से अधिक मूल्य का स्टॉक धारण करते हों जो भारत के निवासी हों अथवा किमी ऐसे अन्य देश के निवासी हों जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों और निगमों को पारस्परिक छूट प्रदान करता है, अथवा

(2) निगम के स्टॉक का मूलतः और नियमित रूप से भारत में किसी स्थापित सेक्यूरिटी बाजार में व्यापार किया जाता है अथवा निगम का स्टॉक किसी ऐसे निगम द्वारा पूर्णतः धारित है जिसके स्टॉक का उसी प्रकार व्यापार किया जाता है और जो भारत में संगठित भी हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार यह समझती है कि यह टिप्पणी तथा आपकी उत्तर टिप्पणी, जिसके तहत यह पुष्टि की गई है कि भारत सरकार इन शर्तों को मानती है, दोनों ही दिनांक 26 नवम्बर, 1976 के करार और दिनांक 27 और 29 दिसम्बर, 1976 के पत्रों के आदान प्रदान को संशोधित करने वाला एक करार है। यह करार मंत्रालय की उत्तर टिप्पणी की तारीख को लागू होगा और दिनांक 1 जनवरी, 1987 को या इसके पश्चात् आरम्भ होने वाले करारधेय वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा।

सकल आय में जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से प्राप्त सभी प्रकार की आय भी शामिल है जिसमें जलयानों अथवा वायुयानों के पूर्णकालिक या जलयानों की अवधि के आधार पर किराए से हुई आय भी शामिल है। इस आय में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त जलयानों और वायुयानों के बेअरबोट के आधार पर किराए से हुई आय, अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त आवाहनों और उनसे संबंधित उपकरणों के किराए से प्राप्त आय, और जलयानों अथवा वायुयानों की बिक्री पर प्राप्त लाभ भी शामिल है, बशर्ते प्रत्येक मामले में वह आय जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन के कारण प्राप्त हुई प्रासंगिक आय हो। जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से होने वाली सकल आय में किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन अभिकरण में भाग लेने से उद्भूत आय और जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित निधियों पर प्राप्त होने वाला व्याज भी शामिल है।

दोनों सरकारों में से कोई भी सरकार राजनयिक माध्यमों से इस करार की समाप्ति या लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकती है।

मैं इस अवसर पर आपको अपनी परम भावना का आभवादन एक बार फिर देता हूँ।

मुझे यह पुष्टि करने हुए प्रसन्नता होती है कि आपकी टिप्पणी और यह उत्तर-टिप्पणी दिनांक 26 नवम्बर, 1976 के करार और दिनांक 27 तथा 29 दिसम्बर, 1976 के पत्रों के आदान-प्रदान को संशोधित करने वाला, दोनों सरकारों के बीच निष्पक्ष एक करार है। यह करार राज की तारीख से लागू होगा और दिनांक 1 जनवरी, 1987 को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा।

महामहिम

डा. नीतीश मेनगुप्ता,

मन्त्रि (राजस्व)

जित्त मंत्रालय

भारत सरकार

डा. जान भार ह्यूबर्ड

राजदूत

कोनो सरकारों में से कोई भी सरकार राजनयिक माध्यमों से इस करार की समाप्ति का लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकती है।

मैं इस अवसर पर आपको अपनी परम आदर भावना का आश्वासन एक बार फिर देता हूँ।

महामहिम

डा. जॉन बार. हम्बर्ग

राजदूत

संयुक्त राज्य अमेरिका

नई दिल्ली।

डा. नीतीश सेन गुप्ता  
सचिव (राजस्व)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 1989

#### Income-Tax

G.S.R. 626(E).—Whereas the annexed Agreement through exchange of letters between the Government of India and the Government of the United States of America for the avoidance of double taxation of income of enterprises operating ships and aircraft has entered into force on the 12th April, 1989, the date of signature thereon by the Contracting States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

Annexure (the letters exchanged to be inserted here)

[F. No. 501/3/86-FTD(Notification No. 8391)]

P.K. APPACHOO, Jt. Secy.

### ANNEXURE

Embassy of the United States  
of America,  
New Delhi,  
April 12, 1989

Excellency,

I have the honour to propose that the Government of the United States of America and the Government of India conclude an agreement to exempt from income tax, on a reciprocal basis, income derived by residents of the other country from the international operation of ships and aircraft. The terms of the Agreement are as follows :

The Government of the United States of America, in accordance with section 872(b) and 883(a) of the Internal Revenue Code, agrees to exempt from

tax gross income derived from the international operation of ships or aircraft by individuals who are residents of India (other than U.S. citizens) and corporations organized in India. This exemption is granted on the basis of equivalent exemptions granted by India to citizens of the United States (who are not residents of India) and to corporations organized in the United States (which are not subject to tax by India on the basis of residence).

In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets either of the following conditions :

- (1) More than 50 percent of the value of the corporation's stock is owned, directly or indirectly, by individuals who are residents of India or of another country which grants a reciprocal exemption to U.S. citizens and corporations, or
- (2) the corporation's stock is primarily and regularly traded on an established securities market in India or is wholly owned by a corporation whose stock is so traded and is also organized in India.

For purposes of sub-paragraph (1), the Government of India will be treated as an individual resident of India. For purposes of the exemption from U.S. tax, sub-paragraph (1) will be considered to be satisfied if the corporation is a "controlled foreign corporation" under the Internal Revenue Code.

Gross income includes all income derived from the international operation of ships or aircraft, including income from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis. It also includes income from the rental on a bareboat basis of ships and aircraft used in international transport, income from the rental of containers and related equipment used in international transport, and gain on the disposition of ships or aircraft, provided in each case that the income is incidental to the international operation of ships or aircraft. Gross income from the international operation of ships or aircraft also includes income derived from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency and interest on funds connected with the international operation of ships or aircraft.

The Government of the United States of America considers that this Note, together with your reply Note confirming that the Government of India agrees to these terms, constitutes an agreement amending the agreement of November 26, 1976 and the exchange of letters of December 27 and 29, 1976. This agreement shall enter into force on the date of your reply Note and shall have effect with respect to taxable years beginning on or after January 1, 1987.

Either government may terminate this agreement by giving written notice of termination through diplomatic channels.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

JOHN R. HUBBARD, Ambassador

His Excellency  
Dr. N.K. Sengupta  
Secretary (Revenue)  
Ministry of Finance  
Government of India

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
New Delhi  
April 12, 1989

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your Note of today's date proposing the terms of a reciprocal exemption from income tax of income derived from the international operation of ships and aircraft.

The Government of India agrees to exempt from income tax gross income derived from the international operation of ships or aircraft by U.S. citizens (who are not residents of India) and corporations organized in the United States (other than corporations which are subject to tax by India on the basis of residence).

In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets either of the following conditions :

- (1) More than 50 percent of the value of the corporation's stock is owned, directly or indirectly, by individuals who are citizens of the United States or residents of another country which grants a reciprocal exemption to Indian residents and corporations or

- (2) The corporation's stock is primarily and regularly traded on an established securities market in the United States, or is wholly owned by a corporation whose stock is so traded and which is also organized in the United States.

Gross income includes all income derived from the international operation of ships or aircraft, including income from the rental of ship, or aircraft on a full (time or voyage) basis. It also includes income from the rental on a bareboat basis of ships and aircraft used in international transport, income from the rental of containers and related equipment used in international transport, and gain on the disposition of ships or aircraft, provided in each case that the income is incidental to the international operation of ships or aircraft. Gross income from the international operation of ships or aircraft also includes income derived from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency and interest on funds connected with the international operation of ships or aircraft.

I am pleased to confirm that Your Excellency's Note and this reply Note constitute an agreement between the two governments amending the agreement of November 26, 1976 and the exchange of letters of December 27 and 29, 1976. This agreement shall enter into force on today's date and shall have effect with respect to previous years beginning on or after January 1, 1987.

Either government may terminate this agreement by giving written notice of termination through diplomatic channels.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

N.K. SENGUPTA, Secy.  
(Revenue)

His Excellency  
Dr. John R. Hubbard  
Ambassador  
United States Embassy  
New Delhi